

दैनिक

रोकथोक लेखनी

खबरें बे-रोकथोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

मिलिंद देवड़ा ने बढ़ाई उद्धव गुट की टेंशन तो कांग्रेस भी तय करेगी उम्मीदवार...

दक्षिण मुंबई से ताल ठोकने का किया इशारा!

मुंबई : महाविकास अघाड़ी के घटक दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद और बढ़ने लगे हैं। पहले से 23 सीटों की मांग कर रही शिवसेना के लिए उसके मौजूदा सांसदों को उनके क्षेत्र उम्मीदवारी दिलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। हाल ही में ऐसा तब देखने को मिला जब कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने ठाकरे समूह को दक्षिण मुंबई सीट पर दावा करने से बाज आने को कह दिया। बता दें कि दक्षिण मुंबई से शिवसेना के अरविंद



सावंत सांसद हैं। वर्ष 2019 में सावंत ने देवड़ा को हराकर दक्षिण मुंबई की सीट जीती थी। गठबंधन के नियमों के अनुसार गठबंधन में शामिल पार्टी के सांसदों व विधायकों वाली सीटों पर

उसी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होता है। लेकिन देवड़ा ने उद्धव गुट के नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ठाकरे गुट दक्षिण मुंबई पर दावा

करेगा तो कांग्रेस भी दावा करेगी और उम्मीदवार तय कर देगी। उन्होंने ये बयान एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल को दिए साक्षात्कार के दौरान कही।

50 वर्षों से हम यहां से लड़ रहे हैं...

महाविकास अघाड़ी के घटक दलों में से एक दल दक्षिण मुंबई सीट पर एकतरफा दावा कर रहा है, कल गिरगांव की बैठक में उसी घटक दल ने एक बार फिर दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट के लिए दावा ठोका। जबकि पिछले 50 वर्षों से दक्षिण मुंबई लोकसभा क्षेत्र पर कांग्रेस का कब्जा रहा है और देवड़ा परिवार इस क्षेत्र से चुनाव लड़ता रहा है। सांसद हो या न हों, हम किसी लहर में नहीं चुने गये। मिलिंद देवड़ा ने यह भी कहा कि हमने इस लोकसभा क्षेत्र में अब तक काम और रिश्तों से जीत हासिल की है। मिलिंद देवड़ा ने कहा, ‘मेरे मतदाता कार्यकर्ता समर्थक मुझे सुबह से फोन कर रहे हैं। इसलिए किसी को भी सार्वजनिक बयान या दावा नहीं करना चाहिए। ऐसी नसीहत भी देवड़ा ने शिवसेना को दी है।

तलाठी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की सबूत मिलने के बाद मामले की जांच की जाएगी - फडणवीस

नेता प्रतिपक्ष वडेद्वीवार ने परीक्षा में घोटाले का लगाया था आरोप



मुंबई : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तलाठी भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा अतिशय पारदर्शिता तरीके कराई गई है। कुछ लोग बिना तथ्य के परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। अगर परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी का सबूत देने वाले की जांच की जाएगी। साक्ष्य सही होने पर जांच कर परीक्षा रद्द कर दोषियों पर कार्रवाई की जायेगी। फडणवीस ने कहा कि राज्य में प्रत्येक परीक्षा को पारदर्शी तरीके कराई जा रही है। लेकिन कुछ लोग बिना तथ्य के परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। अगर परीक्षा में गड़बड़ी का कोई सबूत है उन्हें देना चाहिए सबूत मिलने के बाद परीक्षा को स्थगित कर जांच की जाएगी।

वडेद्वीवार ने ट्वीट में क्या कहा?

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेद्वीवार ने तलाठी भर्ती परीक्षा बड़ा घोटाले का आरोप लगाया है। इस पूरे घोटाले की एसआईटी जांच की मांग की है। रविवार को एक्स पर ट्वीट कर वडेद्वीवार ने कहा कि अगर किसी अभ्यर्थी को 200 में से 214 अंक मिल रहे हैं तो यह स्पष्ट है कि पूरी परीक्षा प्रणाली कितनी गंभीरता से काम कर रही है और सत्तारूढ़ दल ने भर्ती में किस तरह से धांधली की है। इस पूरे मामले की जांच एसआईटी से होनी चाहिए।

कोलाबा में चाली की सुरक्षा दीवार गिरने से एक की मौत!



मुंबई : दक्षिण मुंबई के कोलाबा में एक चाली की सुरक्षात्मक दीवार गिरने से एक हादसे में एक इस्मा की मौत हो गई। हादसा रविवार दोपहर करीब तीन बजे हुआ। इस हादसे में मोहम्मद अकबर की मौत हो गई। हादसा कोलाबा के कफ परेड इलाके में केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 के पास मिया चाली, गजाली दरगाह इलाके में हुआ। दोपहर करीब तीन बजे चाली की सुरक्षा दीवार अचानक गिर गई। उस दीवार के नीचे 38 साल का युवक मोहम्मद अकबर दब गया। उसे बाहर निकालकर पास के अश्विनी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन डॉक्टरों ने इलाज से पहले ही उसे मृत घोषित कर दिया।

अंधेरी कुर्ला मार्ग फुटपाथ पर बोलाई... परेशानी का सबब

मुंबई : फुटपाथों पर लगे स्टील के खंभों (बोल्लार्ड) को लेकर हाई कोर्ट ने नगर पालिका को फटकार लगाई है। इस बोल्लार्ड से अंधेरी के नागरिकों को भी परेशानी हो रही है। ये बोल्लार्ड अंधेरी कुर्ला मार्ग पर चकला से जेबी नगर तक जगह-जगह लगे हुए हैं और इससे विकलांगों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी परेशानी होती है। फुटपाथ पर लगे स्टील पोस्ट (बोल्लार्ड) के बीच की दूरी कम होने के कारण व्हीलचेयर चलाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस मामले को हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है और पिछले हफ्ते कोर्ट ने नगर निगम प्रशासन को कड़े शब्द सुनाए हैं। नगर निगम की ओर से कोर्ट में गारंटी दी गई कि इन बोल्लार्ड के बीच की दूरी एक मीटर रखी जाएगी। शिवाजी पार्क के करण शाह ने जज को बताया कि किस तरह फुटपाथ पर लगे बोल्लार्ड विकलांगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। शाह जन्म से ही विकलांग हैं। शाह के ई-मेल के चलते कोर्ट ने ये जनहित याचिका दायर की थी। इसलिए मुंबई



के फुटपाथों पर बोलाई का मुद्दा सामने आया है। सामाजिक कार्यकर्ता पिमेंटा गॉडफ्रे ने शिकायत की है कि मुंबई में कई जगहों पर ऐसे बोलाई लगाए गए हैं और इससे नागरिकों को परेशानी हो रही है। उन्होंने इस बोल्लार्ड को हटाने की भी मांग की है।

परेशानी हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है। पिमेंटा ने शिकायत की है कि अंधेरी ईस्ट इलाके में चकला से जेबी नगर तक एक किलोमीटर के इलाके में कई जगहों पर ऐसे बोलाई लगाए गए हैं और इससे नागरिकों को परेशानी हो रही है। उन्होंने इस बोल्लार्ड को हटाने की भी मांग की है।

बंदूक साफ करते समय गोली लगने से तीन घायल... वागले एस्टेट में घटना

ठाणे : वागले एस्टेट के रोड नंबर 28 इलाके में बंदूक साफ करते समय गोली चलने से बंदूकधारी समेत तीन लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान मोहम्मद शेख (50), विपीन जयसवाल (21) और राहुल जयसवाल (23) के रूप में हुई है। देर रात तक श्रीनगर थाने में केस दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही थी। रोड नंबर 28 के राम नगर इलाके में चामुंडा फैब्रिकेटर्स नाम की कंपनी है।



इस कंपनी का मालिक मोहम्मद शेख है और विपीन और राहुल उसकी कंपनी में कर्मचारी हैं। शनिवार रात मोहम्मद कंपनी में बंदूक साफ कर

रहा था। तभी गलती से मोहम्मद को गोली लग गयी। यही बात विपीन और राहुल के साथ भी हुई। तो, मोहम्मद की हथेली घायल हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद श्रीनगर पुलिस उपायुक्त अमर सिंह जाधव समेत मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोहम्मद के पास बंदूक का लाइसेंस है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में केस दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है।

संपादकीय / लेख



फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

हिमाचली फरियाद का दर्द

हिमाचल के वित्तीय हालात प्रदेश को फरियादी बना चुके हैं या हमने अपने अर्थतंत्र के तमाम सबूतों को केंद्र के पास गिरवी रख दिया। भले ही डबल इंजन सरकार के पह्रावे में पूर्व सरकार के पांच साल निकल गए या अब व्यवस्था परिवर्तन की राह पर कांग्रेस सरकार की जहोजहद सामने आ गई, लेकिन पर्वतीय प्रदेश का वजूद अब केंद्र का खिलौना बना नट्टार आ रहा है। केवल एक बार धूमल सरकार के वक्त में तत्कालीन

प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने हिमाचल को गले लगाया और आगे बढ़े की प्रेरणा दी, अन्यथा ढोल-ढमाकों ने सिर्फ सियासी घोंसलों में सपने ही दिए। प्रदेश के गले में लटक आरसी हजार करोड़ का ऋण, वित्तीय संसाधनों की कमी और ऊपर से प्राकृतिक आपदा से रूबरू होने का दर्द अब दरबारी बनकर दिल्ली सरकार के समक्ष धूम रहा है। एक साल की कसरतों ने कितने भी ढोए आंसू, मगर सियासत का रेगिस्तान इन्हीं का प्यासा रहा। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मुलाकात के क्षण और केंद्रीय राहत के पन्ने दर्द से भरे हैं, लेकिन इंतजार है उस घड़ी का जब बरसात की त्रासदी को केंद्र से राहत का पैगाम मिले। आपदा के बाद जरूरतों का मूल्यांकन 9727 करोड़ की आशा में केंद्र को टुकड़-टुकड़ पुकार रहा है और यही दरखास्त लिए मुख्यमंत्री देश से अपने हक की फरियाद करते हैं। यह दीगर है कि प्रदेश ने अपने स्तर पर राहत पैकेज के तहत 4500 करोड़ की राशि तय की और हर प्रभावित के मन में दस्तक दी। हिमाचल की यह वही जनता है जिसके सामने प्रधानमंत्री स्वयं रोड शो करते हुए आश्वासन की मुद्रा में केंद्र की गारंटी बने नट्टार आते थे। एक साल पहले हिमाचल के साथ केंद्र के रिश्ते अब क्यों सियासी पाला बदल कर बहरे हो गए या यहां की पूरी जनता दोषी हो गई। क्या प्राकृतिक त्रासदी में भी सियासी विरोध के सुर सुने जाने चाहिए या यह मान लिया जाए कि अगले कुछ साल यह प्रदेश सियासी नरक के जख्म इसलिए ढोएगा क्योंकि केंद्र में दूसरी पार्टी का बादशाह बैठा है।

वोट के बीच मतांतर देखने की दूरबीन अगर यूँ ही निरीह व रूठी रही तो यह मानना पड़ेगा कि हिमाचल को वित्तीय संकट में फँसाने के लिए केंद्र सरकार भी बहाने बना रही है। वित्तीय प्रबंधन की अति कठिन परीक्षा में सुक्खू सरकार के लिए केंद्र सरकार का रवैया फिलहाल मुफीद नहीं है। अड़चनों की फेहरिस्त में राज्य की मजबूरियों को बढ़ाकर सत्तर लाख लोगों का अपमान करना अगर राजनीतिक सौगात है, तो हिमाचल के भाजपा विधायक व सांसद भी क्यों न जिम्मेदार समझे जाएं। इसी जनता ने कल अगर भाजपा को आसन दिया तो आज कांग्रेस को मिले बहुमत को मिल रही यह सजा, वास्तव में प्रदेश के जनादेश का ही विरोध है। केंद्र गारंटी बनाम गारंटी, जीएसटी बनाम जीएसटी, योजना बनाम योजना और परियोजना बनाम परियोजना चुनने लगा तो हिमाचली इच्छाओं, संभावनाओं, विकास और दायित्व का वित्तीय पोषण ईमानदारी से नहीं होगा। अर्थव्यवस्था के हर तंत्र और विकास के हर रास्ते को केंद्र सरकार का शुभ संदेश चाहिए वरना इन हालात में सिर्फ छिंटाकशी मिलेगी। हिमाचल में बाहरी संसाधनों से विकास के रास्तों पर भी संकट आ खड़ा हुआ है। वित्तीय पोषण के बाहरी स्रोतों से पहले ही चौदह हजार करोड़ की परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। इसी रास्ते से वर्तमान सरकार कांगड़ा को पर्यटन राजधानी व पूरे प्रदेश के टूरिज्म डिवेलपमेंट पर 2800 करोड़ की योजना को अमलीजामा पहनाना चाहती है, लेकिन शर्तों की कठिनाई में अगले कुछ सालों तक धन उपलब्ध नहीं होगा। मंडी के शिवधाम व धर्मशाला के कानवेंशन सेंटर पर इस तरह ग्रहण लग रहा है। जाहिर है इन परिस्थितियों में प्रदेश सरकार को एक ओर कठिन वित्तीय फैसले लेने पड़ेंगे, तो दूसरी ओर निजी निवेश के लिए प्रोत्साहन की खिड़कियां चारों ओर खोलनी पड़ेंगी। पहले ही बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को निश्चित समय पर पगार न मिलने से असंतोष पनप रहा है और अगर खजाने में इसी तरह की अनिश्चितता रहेगी तो दबाव में सरकार के लिए कटौतियों का ही इलाज होगा। वित्तीय कटौतियों के कारण विकास पर पड़ वाला प्रभाव प्रदेश के लिए माकूल नहीं हो सकता, जबकि दूसरी ओर गारंटियों की फेहरिस्त कंकाल बनकर डरा रही है। ऐसे में दिल्ली हाजिरी से प्रदेश कितना व क्या हासिल कर पाता है, इसके ऊपर काफी कुछ निर्भर करता है।

+91 99877 75650
editor@rokhoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

सीट-बंटवारे को लेकर एमवीए-इंडिया में घमासान; किसी के पास नहीं महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग फॉर्मूला

मुंबई: चुनावी वर्ष 2024 शुरू हो चुका है। ऐसे में देश के सभी राजनीतिक दल आगामी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए रणनीतियां बना रहे हैं। विचार-मंथन जारी है और पार्टियां नारे गढ़ने में व्यस्त हैं। सभी राजनीतिक दल चाहे सत्तारूढ़ हों या विपक्ष में, केंद्र में हों या राज्य में, पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं और हर कीमत पर जीत का लक्ष्य रख रहे हैं। महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है, जहां शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एपी) की सत्तारूढ़ महायुति और कांग्रेस-शिवसेना (यूबीटी)-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) का विपक्षी महाविकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन है, साथ ही उनके संबंधित छोटे सहयोगी/साझेदार, एक-दूसरे पर हमला करने और जीतने के लिए तैयार हैं। बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश (80 लोकसभा सीटों) के ठीक बाद महाराष्ट्र 48



सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र राष्ट्रीय विपक्षी कठ.ऊकअ. गठबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य है। मई 1960 में अपनी स्थापना के बाद कांग्रेस ने लगभग 50 वर्षों तक राज्य पर शासन किया है। गैर-कांग्रेस गठबंधनों ने 1995-1999, 2014-2019 तक तीन बार शासन किया है। अब एमवीए के पतन के बाद जून 2022 से बीजेपी गठबंधन शासन कर रहा है। हालांकि, शरद पवार, उद्धव

ठाकरे, नाना पटोले जैसे एमवीए के शीर्ष नेताओं के 'ऑल इज वेल' के साहसी दावे किए हैं। इसके बावजूद, तीनों दलों ने अभी तक लगभग 'इंडिया' गठबंधन की तरह अपने प्रस्तावित 'सीट-बंटवारे' फॉर्मूले की घोषणा नहीं की है। महायुति के लिए बहुत खुशी की बात यह है कि एमवीए साझेदार 48 सीटों को लेकर झगड़ते रहे हैं, जबकि वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) जैसे अन्य दावेदार अपने

हिस्से के लिए बाहर इंतजारे कर रहे हैं। एक अजीब नजारा सामने आया है जहां एसएस-यूबीटी और कांग्रेस लगभग 23-24 सीटों की मांग कर रहे हैं, एनसीपी (एसपी) ने अभी तक कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है, जबकि वीबीए कम से कम 12 सीटों पर दावा कर रही है। एसएस-यूबीटी का दावा और गणना 2019 में अविभाजित शिवसेना के रूप में उसकी जीत पर आधारित है। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि अब मूल रूप से चुने गए अधिकांश सांसद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। इस पर पलटवार करते हुए, एसएस-यूबीटी ने बताया कि 2019 में कांग्रेस को केवल 1 लोकसभा सीट मिली, जबकि एनसीपी (एसपी) ने 4 सीटें जीतीं। कांग्रेस नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि एसएस ने जिन 18 सीटों पर जीत हासिल की, उनका वोट शेयर 23.5 प्रतिशत था।

नफरत भरे भाषणों के लिए भाजपा विधायक नितेश राणे और राजा सिंह पर मामला दर्ज



मुंबई : महाराष्ट्र के सोलापुर में हिंदू जन आक्रोश रैली के दौरान नफरत भरे भाषणों के लिए भाजपा विधायक नितेश राणे और पार्टी के तेलंगाना विधायक टी राजा सिंह और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जेल रोड पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने कहा कि रैली शनिवार को राजेंद्र चौक और कन्ना चौक के बीच आयोजित की गई थी। इसमें सकल हिंदू समाज के नेताओं ने भी भाग लिया था, जो कई संगठनों का एक संघ है। इस संगठन के पदाधिकारियों का नाम भी एफआइआर में है। अधिकारी ने बताया कि रैली में जहां राणे ने जिहादियों और मस्जिदों के विध्वंस का जिक्र किया, वहीं हैदराबाद के गोशामहल से विधायक राजा सिंह ने लव जिहाद पर आपत्तिजनक बयान दिए। उन्होंने कहा कि हमने राणे, राजा सिंह, सकल हिंदू समाज के पदाधिकारी सुधाकर महादेव बहिरवाड़े और 8-10

अन्य पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

जीतेंद्र आक्काड के खिलाफ भायंदर में भी मामला दर्ज

भायंदर: विधायक जितेंद्र आक्काड द्वारा राम के बारे में दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर भायंदर के नवघर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में बजरंग दल ने शिकायत दर्ज कराई है। राष्ट्रवादी पार्टी के विधायक जितेंद्र आक्काड ने हाल ही में बयान दिया था कि राम बहुजन हैं और मांसाहारी हैं। इसे लेकर पूरे राज्य में माहौल गरमा गया है। हालांकि आक्काड ने इस पर अफसोस जताया है, लेकिन विवाद सुलझ नहीं सका है। इसके चलते

पूरे प्रदेश के पुलिस स्टेशनों में उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। बजरंग दल ने भी आक्काड के खिलाफ भायंदर में शिकायत दर्ज कराई है। इसके मुताबिक, पुलिस ने एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में आक्काड के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (ए) के तहत मामला दर्ज किया है।

मुंबई में भी सर्दी का आगाज; तापमान पहुंचा 17.5 डिग्री सेल्सियस

मुंबई: उत्तर भारत के साथ महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी सर्दी का आगाज हो गया है। मुंबई में शनिवार इस सीजन का सबसे ठंड दिन रहा। शनिवार को शहर का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। उपनगर का न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 17.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, ठंड के बीच 7 से 9 जनवरी के दरमियान बूढ़ाबांदी की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ राजेश कपाड़िया ने बताया कि उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण रात के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने कहा कि इस ठंड



के बीच मुंबई और आसपास के क्षेत्र में हल्की बारिश भी हो सकती है। अरब सागर से पूर्व की तरफ आने वाली नम हवाएं राजस्थान में सिस्टम (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के साथ मिलने के कारण मुंबई व आसपास के क्षेत्र में बादल छाए रहेंगे और 7 से 9 जनवरी के

बीच बूढ़ाबांदी के आसार हैं। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली संस्था स्काईमेट के प्रमुख मेट्रोलोजिस्ट महेश पलावत के अनुसार दक्षिण अरब सागर में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। यह अगर उत्तर की ओर बढ़ता है, तो एमएमआर के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है।

मुंबई में एटीएस की बड़ी रेड... 6 लोगों को किया गिरफ्तार दिल्ली-UP के रहने वाले हैं सभी...



मुंबई : महाराष्ट्र पुलिस की आतंकरोधी इकाई एटीएस ने मुंबई के बोरीवली इलाके में रविवार दोपहर छापेमारी की है। इस दौरान 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ATS से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इन लोगों के पास से 4 पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। ये सभी लोग दिल्ली और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो एक बड़ी वारदात को

अंजाम देने मुंबई आए थे। महाराष्ट्र एटीएस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 'मुंबई के बोरीवली इलाके में स्थित एक गेस्ट हाउस पर छपा मारकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 3 बंदूकें तथा 36 जिंदा कारतूस बरामद किए। गिरफ्तार किये गये सभी लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। आगे की जांच की जा रही है।'

ईमेल भेजने वाले का उस आईपी एड्रेस जांच के लिए विशेष टीम का गठन

मुंबई : पुलिस ने उन ई-मेल की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है, जिसमें धमकी दी गई है कि शहर में कई स्थानों पर बम विस्फोट किए जाएंगे। एक अधिकारी ने शनिवार को यहा जानकारी दी।

कोलाबा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि टीम के एक ईमेल भेजने वाले का उस आईपी एड्रेस से पता लगाने की कोशिश कर रही है, जहां से ये भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि मेल एक ही ईमेल आईडी से भेजे गए थे और भेजने वाले की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। कोलाबा में छत्रपति शिवाजी



महाराज संग्रहालय के प्रबंधन को एक ईमेल मिला था। जिसमें कहा गया था कि वली स्थित संग्रहालय के नेहरू विज्ञान केंद्र और मध्य मुंबई में बायकुला में चिड़ियाघर सहित आठ से अधिक स्थानों पर बम रखे गए हैं। इसके बाद अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। ईमेल में जिन

अन्य संस्थानों के नामों का जिक्र किया गया है, उनको भी यही धमकी मिली है।

अधिकारी ने बताया कि बम निरोधक दस्ते ने दक्षिण मुंबई में स्थित संग्रहालय की तलाशी ली लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। उन्होंने बताया कि कोलाबा पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (1) (बी) (जनता में भय या चिंता पैदा करने के इरादे से अफवाह फैलाना), 506 (2) (आपराधिक धमकी) और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अवैध रूप से रहने के आरोप तीन बांग्लादेशी गिरफ्तार



पालघर : महाराष्ट्र के पालघर जिले में अवैध रूप से रहने के आरोप में तीन बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने चार जनवरी को वसई इलाके में तलाश अभियान चलाया जिसमें पुलिस ने 23 से 45 वर्ष की आयु के तीन लोगों को गिरफ्तार किया। वसई पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपियों के पास भारत में रहने के लिए वैध दस्तावेज नहीं हैं। उन्होंने बताया कि इसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियमों और विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।

3 लाख 65 हजार रुपये कीमत के कुल 246 सामान चुराने का खुलासा...

नवी मुंबई: ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए ग्राहकों द्वारा ऑर्डर किए गए सामान की डिलीवरी करने वाली कंपनी के उल्टे ऑफिस में काम करने वाली एक महिला द्वारा ऑफिस से 3 लाख 65 हजार रुपये कीमत के कुल 246 सामान चुराने का खुलासा हुआ है। महिला का नाम शीतल कदम (22) है और न्हावा-शेवा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। उल्टे सेक्टर-9 स्थित इटेक्स ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्यरत हैं। कंपनी, जिसकी शाखाएं पूरे देश में हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से ग्राहकों द्वारा ऑर्डर किए गए सामान को उनके पते पर पहुंचाने का काम कर रही है। एक सप्ताह पहले मैनेजर ने देखा कि कंपनी की उल्टे शाखा में



पार्सल आइटम से कुछ सामान गायब हैं। इसलिए जब इस ब्रांच के मैनेजर

और अन्य लोगों ने सामान की जांच की तो पता चला कि स्टोर रूम से 3 लाख 65 हजार रुपये के मोबाइल फोन, घड़ियां, कॉस्मेटिक सामान गायब थे। इसलिए जब कंपनी के मैनेजरों ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो पता चला कि शीतल कदम ने करीब 3 लाख 65 हजार रुपये कीमत के 246 सामान चुराए हैं।

30 से 50 फीसदी तक रिटर्न का प्रलोभन, 18 लाख 90 हजार का चूना...

नवी मुंबई: ऐरोली में रहने वाले एक शख्स को एक दिन में 30 से 50 फीसदी तक रिटर्न का प्रलोभन चूना लगाया गया है। इस संबंध में नवी मुंबई पुलिस के साइबर विभाग में मामला दर्ज किया गया है। ऐरोली में रहने वाले कपिल शाह के मोबाइल पर मैसेज आया कि निवेश का अच्छा मौका है। साथ ही उन्हें एक दिन में 30 से



50 फीसदी तक रिटर्न मिलने का भी प्रलोभन दिखाया गया। उनसे कहा गया

कि उन्हें एक लिंक के जरिए निवेश करना होगा। इसके मुताबिक शाह ने पहले दिन अपने खाते में दो हजार रुपये जमा किये थे। शाह को उसी दिन 2,800 रुपये का रिफंड दिया गया। इसलिए शाह ने करीब 1 लाख 50 हजार का निवेश किया था। हालांकि, उनसे कहा गया कि अगर वह मूल राशि के साथ-साथ रिफंड भी चाहते हैं तो 5 लाख 40 हजार रुपये फिर से निवेश करें। ऐसा करते समय शाह ने करीब 18 लाख 90 हजार का निवेश किया था। हालांकि, धोखाधड़ी के बारे में आश्वस्त होने के बाद शाह ने नवी मुंबई के साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है क्योंकि साइबर चोरों द्वारा रिफंड के लिए 28 लाख रुपये की मांग की गई थी।

खोया हुआ सोने का कंगन लौटाकर दिखाई ईमानदारी...

मुंबई: तलवली के अष्टमी गांव निवासी मारुति बामने ने सोने का कंगन लौटाकर ईमानदारी दिखाई है। सचिन मोरे का सोने का कंगन शुक्रवार (5 तारीख) को उनके गांव के निवासी रघुनाथ मारवाड़े के घर पर हल्दी समारोह के दौरान खो गया था। इस कंगन की कीमत करीब 50 से 60

हजार रुपये थी। सोने का कंगन खो जाने से उसे भारी आर्थिक हानि हुई। इस बीच, मारुति बामने को लिंगगहाई के हंगामे में लापता सोने का कंगन मिलता है। मारुति बामने ने तुरंत सरपंच रवींद्र मारवाड़े और अन्य प्रमुख ग्रामीणों से संपर्क किया और उन्हें सोने के कंगन के बारे में जानकारी दी।

सरपंच रवींद्र मारवाड़े और अन्य ग्रामीणों ने अन्य लोगों से संपर्क कर कंगन के बारे में जानकारी दी। इस बीच जब पता चला कि कंगन सचिन मोरे का है तो उनसे संपर्क किया गया और वापस कर दिया गया। इस वजह से मारुति बामने की ईमानदारी की हर जगह सराहना हो रही है।

कल्याण जिला बनाया जाना चाहिए - विधायक किसन कथोरे

डोंबिवली : विधायक किसन कथोरे मांग कर रहे हैं कि ठाणे जिले को विभाजित किया जाना चाहिए और एक अलग कल्याण जिला बनाया जाना चाहिए। उन्होंने अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त किया है कि यह जिला हर हाल में कल्याण जिला बनना चाहिए। साथ ही मुझे इस मांग के लिए केंद्र से संपर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी; लेकिन उन्होंने कहा है कि जिद है कि मुख्यमंत्री जल्द फैसला लें। विधायक कथोरे ने शुक्रवार (5) को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत की। इस समय राज्य में गठबंधन सरकार है। जब विधायक कथोरे से पूछा गया कि क्या अब उनकी अपनी सरकार है तो जिले के बंटवारे की मांग पूरी हो जाएगी तो उन्होंने कहा, मुझे केंद्र के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य के मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों का फॉलोअप किया जा रहा है। कमेटी ने उन पर रिपोर्ट दी है। इस पर राज्य सरकार ने एक कमेटी गठित की थी। उनकी रिपोर्ट भी आ गई है। विधायक कथोरे



ने कहा है कि हमारा आग्रह है कि मुख्यमंत्री जल्द निर्णय लें।

ठाणे जिले के विभाजन की मांग कई वर्षों से की जा रही थी। 2011 में, किसन कथोरे, जो नेशनलिस्ट पार्टी में थे, ने मांग की कि कल्याण को एक अलग जिला बनाया जाना चाहिए। उस समय कल्याण तालुक की आम बैठक में इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव का तत्कालीन विधायक गणपत गायकवाड़ समेत कई

लोगों ने समर्थन किया था। साथ ही, अंबरनाथ, कल्याण, मुरबाड आदि तालुकों की ग्राम सभा में स्थानीय स्व-सरकारी निकायों में भी इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। कथोरे की तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार से भी सकारात्मक चर्चा हुई थी। बताया जा रहा है कि कल्याण जिले के निर्माण को लेकर सरकार द्वारा नियुक्त पिंगुलकर समिति ने भी रिपोर्ट पेश कर दी है कि यह मांग सही है। 2014 में, ठाणे जिले को पालघर जिले में विभाजित किया गया था। पालघर जिले के गठन के बाद भी, ठाणे जिला भौगोलिक, राजनीतिक और प्रशासनिक विस्तार की दृष्टि से विशाल है। ठाणे जिले में तीन लोकसभा क्षेत्रों सहित 18 विधानसभा क्षेत्र हैं। साथ ही विधान परिषद सदस्यों की संख्या भी अधिक है। 24 विधानसभा क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है कि ठाणे जिले को गठबंधन सरकार ने जल्दबाजी में तीन हिस्सों में बांट दिया, जबकि उम्मीद थी कि कम से कम 8 सदस्यों का जिला बनाया जाएगा।

हवा की गुणवत्ता बिगड़ने से नुकसान

वाशी: नए साल की शुरुआत में भी नवी मुंबई में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई थी। वाशी, तुर्भे, जुईनगर, सानपाड़ा इलाकों में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई थी। इसका असर अब स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और बढ़ता प्रदूषण सिरदर्द बनता जा रहा है क्योंकि कई लोग सांस लेने में तकलीफ की शिकायत कर रहे हैं। मॉनसून के बाद नवी मुंबई में वायु गुणवत्ता का स्तर लगातार गिर रहा है। 1 से 7 जनवरी की अवधि के दौरान शहर में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 180 से 300 के आसपास रहा है। लगातार बिगड़ रही हवा की गुणवत्ता का असर अब शहरवासियों के स्वास्थ्य



पर भी पड़ने लगा है। कई लोगों को खांसी, आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ की शिकायत बढ़ गई है। ऐसे में प्रदूषित हवा से गंभीर बीमारियां होने की आशंका रहती है। इसलिए शहर में औद्योगिक आस्थानों के साथ-साथ कारों की बढ़ती संख्या से प्रदूषण और शहर में अवैध निमाणों के कारण उड़ने वाली धूल से प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है।

अलीबाग - विरार कॉरिडोर के खिलाफ किसानों का धरना



उरण: अलीबाग-विरार कॉरिडोर प्रभावित संघर्ष समिति के सदस्यों ने अलीबाग कलेक्टर कार्यालय और अलीबाग में कोंकण आयुक्त कार्यालय द्वारा किसानों की जमीन का कम मुआवजा दिए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है. इस मामले में कोर्ट जाने का भी फैसला किया गया है.

सरकारी भूमि अधिग्रहण विभाग ने वसई अलीबाग कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए उरण में किसानों को नोटिस जारी किया है। इसलिए किसानों में यह भावना है कि

सरकार उन पर अत्याचार कर रही है। साथ ही 2018 की जमीन की कीमत परियोजना प्रभावितों को दिए जाने से किसान ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी तरह, विभिन्न परियोजनाएं आ रही हैं जबकि उरण तीसरी मुंबई की ओर बढ़ रहा है। इसलिए जहां एक ओर जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार के प्रति लोगों में काफी गुस्सा है क्योंकि सरकार किसानों की जमीन को औने-पौने दाम पर लेने की कोशिश कर रही है. इसलिए सरकार की इस किसान विरोधी नीति के खिलाफ अलीबाग-विरार कॉरिडोर प्रभावित संघर्ष समिति ने 12 फरवरी को अलीबाग कलेक्टर और 26 फरवरी को कोंकण कमिश्नरेट पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है.

29 हजार से अधिक फर्जी फर्मों का भंडाफोड़... महाराष्ट्र सबसे आगे



मुंबई : केंद्र सरकार ने बताया है कि फर्जी पंजीकरण के खिलाफ अभियान के दौरान करोड़ों रुपये का राजस्व बचाने में मदद मिली है। जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावे करने वाली 29,273 फर्जी फर्मों का पता लगाया है। इससे 4,646 करोड़ रुपये का राजस्व बचाने में मदद मिली है। आंकड़े दिसंबर 2023 तक के हैं, जिसमें आठ महीनों के दौरान 44,015 करोड़ रुपये के फर्जी दावे किए गए। पहले चार स्थानों पर महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्य हैं। सरकार के मुताबिक अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 4,153 फर्जी कंपनियों का पता लगाया गया। इनमें लगभग 12,036 करोड़ रुपये की संदिग्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट चोरी

शामिल थी। केंद्रीय जीएसटी अधिकारी इनमें से 2,358 फर्जी फर्मों का पता लगा चुके हैं। महाराष्ट्र 926 फर्जी फर्मों के साथ सूची में शीर्ष पर है। इसके बाद राजस्थान (507), दिल्ली (483) और हरियाणा (424) का नंबर आता है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि दिसंबर तिमाही के दौरान 1,317 करोड़ रुपये का राजस्व सुरक्षित करने में सफलता हासिल हुई। 319 करोड़ रुपये की वसूली की गई। 997 करोड़ रुपये की आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवरुद्ध करके सुरक्षित किए गए।

12 फुट के अजगर को सर्प मित्रों ने दिया जीवनदान



मुंबई : उड़दवणे गांव के सर्प मित्र दीपक कोल्हटकर ने 12 फुट के अजगर को जीवनदान दिया है. यहां की एक नहर में ये बड़ा अजगर मिला. सर्प मित्र दीपक कोल्हटकर को मुठावली खुर्द गांव में राम वामन तुपकर के घर के सामने नहर के बेहद दुर्गम इलाके में अजगर होने की जानकारी मिली. बिना एक पल की देरी किए वे मौके पर गए और सहकर्मियों अभय कराले और नयन पाटिल के प्रयासों से बड़ी सफलता के साथ बारह फुट के अजगर को पकड़ा और उसे वन क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया। इस समय बड़े अजगर का प्रतिरोध देख दर्शक भी कांप रहे थे. दीपक कोल्हटकर ने अब तक सैकड़ों अलग-अलग जहरीले और गैर-जहरीले प्रजाति के सांपों की जान बचाई है।

ठाणे, कल्याण में मिल मजदूरों के लिए घर!

मुंबई: राजस्व विभाग द्वारा मिल श्रमिकों के आवास के लिए ठाणे, कल्याण में 54 एकड़ का भूखंड उपलब्ध कराने के संबंध में उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस के साथ एक सकारात्मक बैठक के बाद, महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) ने राजस्व विभाग के भूखंडों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। मुंबई महानगरीय क्षेत्र. म्हाडा ने सभी पात्र मिल श्रमिकों को आवास प्रदान करने के लिए राज्य में कुछ भूखंडों का सर्वेक्षण भी शुरू कर दिया है। म्हाडा के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयसवाल ने म्हाडा में लंबित प्रस्तावों को पट्टी पर लाने के लिए मजबूत प्रयास शुरू कर दिए हैं। पिछले सप्ताह उपमुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में इन सभी मुद्दों पर सकारात्मक रुख अपनाया गया था. इसके बाद म्हाडा ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर सरकार को सौंपना शुरू कर दिया है. कुछ प्रस्ताव राजस्व एवं आवास विभाग के पास लंबित हैं, उनकी समीक्षा कर नया प्रस्ताव भेजा जायेगा. इन घटनाक्रमों से जुड़े सूत्रों ने यह भी कहा कि म्हाडा मिल श्रमिकों के घरों के लिए तुरंत प्लॉट दिलाने की कोशिश कर रही है।



दर से म्हाडा को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। . म्हाडा का इरादा इस भूखंड पर मिल श्रमिकों के लिए 19 हजार घर बनाने का है। इसके अलावा, कुर्ला स्थित स्वदेशी मिल में 122 घर मिल श्रमिकों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। म्हाडा ने यह परीक्षण भी शुरू कर दिया है कि सेंचुरी मिल में म्हाडा को आवंटित जमीन पर मिल श्रमिकों

के लिए 3 से 4 हजार और काला चौकी में 22 हजार वर्ग मीटर जमीन पर घर बनाए जा सकते हैं या नहीं। बताया गया कि यह देखने का प्रयास किया जा रहा है कि इंडिया बुल्स कंपनी द्वारा एमएमआरडीए को दिए गए मकानों के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उपलब्ध 1 लाख 31 हजार 437 मकान मिल श्रमिकों के लिए उपलब्ध कराए जा सकते हैं या नहीं. आरक्षण वाले भूखंडों पर नियमों में बदलाव कर मिल श्रमिकों के लिए मकान खोले जाने का एक बड़ा भूखंड बोरीवली में पड़ा है और इसका परीक्षण किया जा रहा है कि क्या इसका उपयोग मिल श्रमिकों के लिए घरों के लिए भी किया जा सकता है।

दूर होगी खारघर में दुर्गंध की समस्या...

खारघर: खारघर सेक्टर 7, 9 और 11 में सीवेज रिप्रोसेसिंग प्लांट का रखरखाव नहीं होने के कारण इलाके में दुर्गंध फैल रही है और नागरिकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो रही हैं. अस्तित्व में आने के बाद सिडको ने इस केंद्र को पनवेल नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया है। इसलिए नगर निगम ने इस सेंटर के रखरखाव और मरम्मत के लिए बजट तैयार करने के लिए एजेंसी से टेंडर मागे हैं। उम्मीद है कि इस इलाके में दुर्गंध की समस्या दूर हो जायेगी. सिडको ने खारघर सेक्टर 3 से 12 क्षेत्र में सीवेज उपचार के



लिए खारघर सेक्टर सात, सेक्टर नौ और सेक्टर ग्यारह में तीन पंप हाउस स्थापित किए हैं। इन केंद्रों में पानी पंप करने के लिए लगे पंप अक्सर खराब रहते हैं। इसलिए, चूंकि क्षेत्र में पानी पंप नहीं किया जा रहा था, इसलिए सीवेज को नाले में छोड़ने का समय आ गया था। साथ ही बारिश के मौसम

में कई बार सीवर ओवरफ्लो हो जाता था और सीवेज सड़क पर बह जाता था। सेक्टर 4, 5, 11 और 12 में सड़कों पर गंदा पानी बहने के कारण नागरिक बार-बार नगर निगम से शिकायत कर रहे थे। आखिरकार, नागरिक संतुष्ट हैं क्योंकि नगर निगम ने खारघर सेक्टर 7, 9 और 11 में सीवेज रिप्रोसेसिंग सेंटर के रखरखाव और मरम्मत के लिए बजट मांगा है। फिलहाल यह बजट तीन साल के लिए है और इसके बाद एजेंसी नियुक्त कर मार्च के अंत तक काम कराया जायेगा, ऐसा दावा नगर निगम की ओर से किया गया है.

नवी मुंबई के छात्रों ने एआई की शिक्षा ली

नवी मुंबई: नवी मुंबई नगर निगम ने मिशन इनोवेशन प्रोग्राम के माध्यम से छात्रों की रचनात्मकता को नई दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मनपा आयुक्त राजेश नावेंकर के मार्गदर्शन में सकारात्मक कदम उठाए जाने शुरू हो गए हैं. प्रथम चरण में नगर निगम क्षेत्र के 16 विद्यालयों में 500 से अधिक छात्र-छात्राओं को नवोन्मेषी कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया है. इसमें डॉ. डी। वाई पाटिल इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन



सेंटर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस गतिविधि के लिए ग्रॉक लर्निंग प्रा. लिमिटेड इनके माध्यम से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित शैक्षणिक मंच उपलब्ध

कराया गया है। बच्चों की विज्ञान के प्रति रुचि को उचित दिशा देकर उनमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विभिन्न अवधारणाओं को स्वतंत्र रूप से विकसित करने का एक बेहतरीन मंच

प्रदान किया जा रहा है। यह पहल प्रोफेसर आशीष जाधव और उनके सहयोगियों के माध्यम से की गई है। इसी प्रकार, छात्रों के कौशल का उपयोग करके उपलब्ध संसाधनों के भीतर प्रोजेक्ट बनाने का लक्ष्य भी ध्यान में रखा गया है। विभिन्न स्कूलों के 200 से अधिक विज्ञान शिक्षकों को डॉ. द्वारा प्रशिक्षित किया गया। डॉ। वाई प्रशिक्षण पाटिल इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर में दिया गया। यह मुख्य रूप से भविष्य

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर ४ , मदीना मेशन, ८९ ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००९६ , महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 व्हाट्सप्प नं 7977408589: Email-editor@rokthoklekhaninews.com